



राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-2)



JICA द्वारा ऋण एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से संचालित

संवाद पत्र

अंक - 7

जुलाई से सितम्बर 2017

68वें राज्यस्तरीय वन महोत्सव का आयोजन



68वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव 10 जुलाई 2017 को गोविन्दपुरा बीड़ में आयोजित किया गया। माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे तथा माननीय केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बिल्व पत्र के पौधे लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चार एवं विशाल जनसमूह के बीच उन्होंने मौलश्री, गूलर, पीपल, बरगद, खेजड़ी आदि के पौधे लगाए। इसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी वन विभाग एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवर, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत, राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष श्रीयुत श्रीराम वेदिरे, माननीय विधायक श्री अशोक परनामी, जयपुर मेयर श्री अशोक लाहोटी, भारत सरकार के वन महानिदेशक श्री सिद्धांत दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री एन.सी. गोयल तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) श्री ए.के. गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।



इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) के रूप में शुरू हुई जल क्रांति के बाद प्रदेश में वन क्रांति शुरू हो रही है। पिछले वर्ष जल संरक्षण के लिए जिस जनजागृति के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई थी, उसे जन-जन के सहयोग से वन संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़े और अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमजेएसए के

दूसरे चरण में प्रदेश में 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दूदू पंचायत समिति के सिरोही कलां तथा फागी के सांवरियाकलां गांव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एमजेएसए के अंतर्गत किए गए जल संरक्षण कार्यों के कारण इस क्षेत्र में चने की उत्पादकता दोगुनी हो गई। यहां के गांवों में जहां वर्ष में एक ही फसल हो पाती थी, अब दो फसलें मिलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के शुरुआती तीन साल में 12000 गांव मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में कवर हो जाएंगे तथा

परियोजना निदेशक की कलम से ...



हर्ष का विषय है कि परियोजना के सातवें वर्ष की दूसरी तिमाही तक सभी घटकों में भौतिक लक्ष्यों की लगभग शत प्रतिशत उपलब्धि रही है। शेष रहे लक्ष्यों को भी योजनाबद्ध तरीके से समय पर प्राप्त किया जाना है।

इस वर्ष के प्रारंभ से ही हमारा विशेष ध्यान स्वयं सहायता समूहों तथा समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण पर रहा है। हमारा प्रयास है कि परियोजना समाप्ति पर परियोजना अंतर्गत गठित इन आधारभूत संस्थाओं को हम पूर्णरूप से समर्थ एवं आत्मनिर्भर बना सकें। तभी हम साझा वन प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त कर प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपना एक छोटा सा योगदान दे पायेंगे।

सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं।

— आर.के. गोयल (आई.एफ.एस)
परियोजना निदेशक

आने वाले सालों में इस अभियान से राज्य को जल आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। इस अभियान में शहरी क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त कुओं और बावड़ियों को दुरुस्त कर इस अभियान के माध्यम से पारम्परिक जल संरचनाओं को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है तथा वृक्षकुंज तैयार किये जा रहे हैं।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि जल एवं वन संरक्षण के लिए राजस्थान में जिस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे यहां का पर्यावरण तो बेहतर बनेगा ही, साथ ही ऐसे अभियान दुनियाभर के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनकर आएंगे। प्रदेश में पौधारोपण के साथ उनकी जिओ-टैगिंग कराने के नवाचार पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पेड़ों को बचाने और पनपाने के लिए विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जाना प्रशंसनीय है।

उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हिन्दुस्तान की संस्कृति में वनस्पति का बड़ा महत्व है और इस

महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एमजेएसए जैसा अभियान चलाया, जिसकी वजह से हरे-भरे राजस्थान की कल्पना साकार होने की दिशा में है।

राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत कर उनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद भी की। प्रदर्शनी के दौरान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना - 2 के अन्तर्गत प्रदेश के अनेकों जिलों में संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे - मार्बल शिल्प, कैर-सांगरी, हल्दी, कशीदाकारी, लाख चूड़ी, कपड़ा बैग, रली हस्तकला, मिट्टी बर्तन दस्तकारी, दरी बुनाई आदि का प्रदर्शन किया गया।





सफलता की कहानियाँ

खेतों में छाई हरियाली-जीवन में आयी खुशहाली

कुम्भलगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव ढाणा में सन् 2012 में पिपलाज माँ पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन किया गया था। गांव ढाणा के लोगों की आजीविका पशुपालन व मजदूरी पर ही निर्भर थी। किन्तु छोटे खेत तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में केवल मौसमी फसल ही हो पाती थी। इसलिए गांव के अधिकतर पुरुष रोजगार की तलाश में मुम्बई/सूरत पलायन करते हैं।

गांव में आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए परियोजना के अंतर्गत 10 महिलाओं का आम्बेश्वर महादेव नाम से स्वयं सहायता समूह 2 अप्रैल 2013 को गठित किया गया। महिलाओं के समूह की बैठक में स्वयं सेवी संस्था एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं को आजीविका विकास के लिए प्रेरित किया। चर्चा के दौरान पता चला कि यहां पर कृषि व सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त पानी व जैविक वातावरण है। लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण खरीफ की एक ही फसल हो पाती है। समूह के सदस्यों ने बताया कि अभ्यारण्य से निकलने वाले नाले में पर्याप्त पानी रहता है। यदि इसको लिफ्ट किया जाये तो यहां रबी की फसल व सब्जियां भी पैदा हो सकती हैं एवं साथ ही कुंए से भी पानी लिया जाना संभव है। सभी ने तय कर एक ईजन पम्प सेट तथा सिंचाई हेतु पाईप लाईन

खरीदने का निर्णय किया। इस काम के लिए समूह को रुपये 50,000 की सहायता समिति के रिवोल्विंग फण्ड से मार्च 2015 में ऋण के रूप में दी गई। ईजन पम्प सेट खरीदने के उपरांत खेतों की निराई गुड़ाई शुरू की गई तथा रबी की फसल गेहूं 25 बीघा क्षेत्र में बोई गई। इस फसल की 3 बार सिंचाई नाले के पानी से तथा 1 बार सिंचाई कुंए के पानी से की गई। फलस्वरूप गेहूं की फसल पूरे 25 बीघा में लहलहा गई। गेहूं की फसल काटने के बाद महिलाओं ने टमाटर, मिर्ची, भिंडी आदि सब्जी बोन की भी तैयारी कर ली।



परियोजना निदेशकगण की बैठक का आयोजन

देश में JICA द्वारा सहायतित वानिकी परियोजनाओं के परियोजना निदेशकों की बैठक के आठवें संस्करण का आयोजन 18 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न प्रदेशों में संचालित परियोजनाओं के अनुभवों को साझा करना तथा परियोजना क्रियान्वयन से सम्बंधित मुद्दों, चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करना था जिससे क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। वनीकरण, जैव विविधता, भू एवं मृदा संरक्षण, आजीविका संवर्द्धन, आय सृजन गतिविधियां, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सतत वन प्रबंधन के लिए वित्तीय समावेश के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा तथा सरकार, JICA एवं वन अधिकारीयों के बीच आपसी समन्वय बनाने के लिए भी

इस बैठक का आयोजन किया गया था।

इस बैठक को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस. सेल्वाकुमार; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक श्री सौमित्रदास गुप्ता तथा निदेशक, डीईए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री अवनीश कुमार मिश्रा ने सम्बोधित किया। सभी गणमान्य अतिथियों ने भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र में JICA परियोजनाओं के कार्यों और उपलब्धियों की सराहना की।

बैठक के दौरान, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने सतत वन प्रबंधन से सम्बंधित विषयों पर अपनी तकनीकी प्रस्तुतियाँ सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखीं।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-1) के संयुक्त परियोजना निदेशक (प्रशासन) श्री आर.पी. गुप्ता ने अपने प्रेजेंटेशन में परियोजना की अब तक की उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया।



Financial Progress for the period July 2017 to Sept. 2017

Rs. In Lacs.

S. No.	Package / Budget Head	Expenditure upto FY 2016-17	FY 2017-18				Cumulative Expenditure
			BE	Exp. April'17 to June'17	Exp. July'17 to Sept.'17	Total Expenditure 2017-18	
1	Afforestation	47558.60	6260.95	215.00	1958.08	2173.08	49731.68
2	Agro Forestry Activities	40.74	54.74	0.00	2.29	2.29	43.03
3	Water Conservation Structures	4762.64	852.89	0.00	5.48	5.48	4768.12
4	Biodiversity Conservation	10227.17	600.02	50.81	112.20	163.01	10390.18
5	Poverty Alleviation and Livelihood Improvement	450.26	458.50	2.50	0.54	3.04	453.30
6	Capacity Building, Training & Research	232.23	253.18	0.47	0.00	0.47	232.70
7	Community Mobilisation	4836.59	547.97	7.90	2.13	10.03	4846.62
8	Project Management	1831.84	345.70	17.40	31.64	49.04	1880.89
9	Monitoring & Evaluation	161.76	86.00	0.15	2.67	2.82	164.58
10	Contractual Personnel for PMU	988.55	190.05	23.09	60.39	83.48	1072.03
	Total	71090.38	9650.00	317.33	2175.42	2492.75	73583.13
11	Administrative Cost	578.28	150.00	26.91	25.55	52.46	630.74
12	VAT & Import Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	578.28	150.00	26.91	25.55	52.46	630.74
	Grand Total	71668.66	9800.00	344.24	2200.97	2545.21	74213.87

संपादक मण्डल:	संरक्षक आर.के. गोयल परियोजना निदेशक	संपादक आर.पी. गुप्ता संयुक्त परियोजना निदेशक	सहायक संपादक जी. के. वर्मा उप परियोजना निदेशक	संयोजन संयोग मिश्र	साज-सज्जा गिरधारी लाल चौधरी
---------------	--	---	--	-----------------------	--------------------------------

प्रकाशक : राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-2), अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर (राज.) 302004, फोन : 0141-5199660